Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 12, Issue No. 2, January-2017, ISSN 2230-7540

औधोगिक विकास में सार्वजनिक बैंकों की भूमिका

Pankaj Kumar Singh*

Research Scholar, SSSUTMS University, Madhya Pradesh

----------X----------

प्रस्तावना

स्वतंत्रता के बाद विकास को गति देने, मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के निर्माण करने, लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने और समानता तथा न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश में 1951 से आर्थिक योजना की नीति को अपनाया गया। तदोपरान्त प्रारंभ से लेकर अब तक के सारे आयोजनों में योजना प्रक्रिया को मजबूत एवं परिष्कृत करने के प्रयत्नों के साथ ही साथ समाजवादी समाज की संरचना के अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ठोस उपाय भी अपनाये गये है।

नियोजन के विभिन्न आयामों में देश के औद्योगिक विकास एवं प्रगति की अहम भूमिका होती है, तथा संपूर्ण योजनागत उद्देश्यों की प्राप्ति में देश की बैंकिग व्यवस्था से बहुत अधिक आशायें होती है। इसी दृष्टिकोण से भारतीय बैंक व्यवस्था को सुदृढ़ तथा प्रगतिशील बनाने के प्रयास स्वतंत्रता के तुरन्त बाद ही प्रारंभ कर दिए गए। आज देश की बैंकिंग प्रणाली का समुचित विकास हो चुका है, तथा देश की अर्थव्यवस्था पर इसका पर्याप्त प्रभाव भी दृष्टिगत होता है। देश के 90 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है, एवं ऐसा समझा जाता है कि अब ये विभिन्न क्षेत्रों में अधिक सेवा तथा सुविधाऐं उपलब्ध करा पा रहे है, एंव आर्थिक विकास में एक प्रभावी संगठन के रूप में कार्य कर रहे है।

किसी भी अर्थ व्यवस्था के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने में वित्त का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। वित्त की इस उपलब्धता को बनाये रखने में बैकिंग संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्यों कि बैकिंग संस्थाएँ ही अर्थव्यवस्था के उद्योग, कृशि, सेवा तथा व्यापार सभी क्षेत्रों के लिये आवश्यक पूंजी उपलब्ध करातीं हैं। बैंक जनता की बचतों को निक्षेप के रूप में जमा कर उनको उपयोगी क्षेत्रों में विनियोग करते हैं। जिससे देश में पूंजी का निर्माण होता है और देश के विकास में गतिशीलता आती है। राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैकिंग कार्यप्रणाली ठीक इससे विपरीत थी। बैकिंग संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना था, सामाजिक विकास में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। बैकिंग सुविधायें कुछ विशिश्ट वर्गों तक सीमित थी। लाभप्रद स्थानों पर ही शाखाएँ स्थापित की जाती थी। ग्रामीण क्षेत्र बैकिंग सुविधाओं से मीलों दूर थे, या यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण लोग बैंकों से परिचित ही नहीं थे। गांवों में सेठ–साहूकारों का प्रभुत्व था, जो आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा सकता है। वर्तमान समय में सागर संभाग में निम्न सार्वजनिक क्षेत्र के राश्ट्रीयकृत बैंक कार्यरत हैं। जो सागर संभाग के औद्योगिक विकास में आवश्यक भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं :– स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, इलाहाबाद बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, आंध्रा बैंक, इंडियन बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स, आदि।

अब तक इस क्षेत्र में किये गये शोध साहित्यों की समीक्षा

शर्मा, अनिल कुमार : (1982) ने अपने शोध प्रबंध ''सागर संभाग में औद्योगिक विकास की समस्याऐं एवं संभावनाऐं'' में स्पष्ट किया है कि संभाग का समुचित विकास करना है, तो संभाग में कृषि आधारित उद्योग, पशुपालन, मछली पालन, बागवानी, कुटीर उद्योग का विकास करना होगा, जो सागर संभाग में रोजगार के अवसर उपलब्ध करायेगा। संभाग के ग्रामों में उद्योग स्थापित किये जाने चाहिऐं एवं इनमें संभाग के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने चाहियें। सागर संभाग की विशाल प्राकृतिक संपदा, उर्वराभूमि, परिश्रमी श्रमिक आदि एक प्रगतिशील औद्योगिकरण के बहुस्तरीय प्रयोजना विकास हेतु अच्छी पृष्ठभूमि प्रदान करें। जो कि शासकीय सहयोग द्वारा पूरा हो सकता है। एवं इसकी सहायता से संभाग का बहुस्तरीय विकास भी संभव होगा।

जैन, मनीष कुमार : (2004) ने अपने शोध प्रबंध ''सागर संभाग के औद्योगीकरण में जिला उद्योग केन्द्रों की भूमिका का आलोचनात्मक अध्ययन'' में स्पष्ट किया है कि जिला उद्योग केन्द्रों में जिला स्तर पर औद्योगीकरण की कार्य प्रणालियों की व्यवस्था सुधार हेतु आवश्यक परिवर्तन किये जाने चाहिये। जिला उद्योग केन्द्रों की पहुँच सभी ग्रामों तक संभव नहीं होती अतः ऐंसी योजनायें बनानी चाहिये जो विकासखंड स्तर पर भी व्यवस्थित ढंग से कार्य करें। जिला उद्योग केन्द्र नये औद्योगिक पर्यावरण के निर्माण में सहयोगी अवश्य हुए है, किन्तु ग्रामीण संसाधनों का संपूर्ण उपयोग अभी संभव नहीं हो पाया, अतः वर्तमान में भी ऐंसे सतत् प्रयासों की आवश्यकता है, जिससे संभाग का विकास संभव हो।

मिश्रा, सुनीता : (2005) ने अपने शोध प्रबंध ''मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास की नवीन प्रवत्तियाँ (1991 के पश्चात्)'' में स्पष्ट किया है कि भारत में (1991 से 1997) तक सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्रों में रोजगार की मात्रा बढ़ी है लेकिन उसके पश्चात् प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम होते जा रहे है। वृहद एवं मध्यम आकार की औद्योगिक इकाईयों में मुख्यतः कृषि

www.ignited.in

आधारित उद्योग, सूति, पटसन, मानव निर्मित रेशा उद्योग एवं रसायन आधारित उद्योग, आयरन एवं स्टील, उत्पाद उद्योग, मिश्रित धातु उद्योग अधिक संख्या में स्थापित किये गये है। किन्तु इन उद्योगों में वृद्धि 1991 से 1998 तक रही। इसके बाद के वर्षो में इन की संख्या व इनमें पूंजी निवेश तथा रोजगार में निरंतर कमी सामने आई है। विभिन्न वित्तीय संस्थाओं की पहुँच ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, जिससे संभाग में ग्रामीण औद्योगीकरण का विकास नहीं हो सका है।

प्रस्तावित शोध में महत्वपूर्ण योगदान

सिद्दीकी, आफताब अहमद : (2000) ने अपने शोध प्रबंध ''सागर संभाग में औद्योगिक उदारीकरण के प्रभावों का मूल्यांकन'' में स्पष्ट किया है कि संरक्षणवाद से उदारवाद की नीतियों की ओर परिवर्तन ने संभाग को विदेशी पूंजी निवेश एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी से वंचित रखा है एवं बहुराष्ट्रीय निगमों की आक्रामक कार्यशैली ने संभाग के लघु व कुटीर उद्योगों के समक्ष अपने अस्तित्व को बचाये रखने का संकट पैदा कर दिया है। हमें इस मार्ग को छोड़ना होगा क्योंकि इसमें लाभ की अपेक्षा हानि अधिक है। हमें मध्य के मार्ग को अपनाना होगा और आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ चयनात्मक उदारीकरण का मार्ग अपनाना होगा। उदारीकरण ने राज्यों के छिन्न–भिन्न हो रही अर्थव्यवस्था, बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, आय की आसमानता एवं क्षेत्रीय औद्योगिक असंतुलन में वृद्धि ही की है। अतः सरकार को उदारीकरण के इस मायाजाल से निकलकर बुनियादी समस्याओं की ओर ध्यान देना होगा, तथा स्वदेशी की अवधारणा को विकसित करना होगा, क्योंकि संभाग के औद्योगिक विकास के लिए यही एक उचित मार्ग है।

पस्तुत शोध प्रबंध के उद्देश्य

- औद्योगिक विकास की अवधारणा का अध्ययन करना।
- सागर संभा के औद्योगिक विकास में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका का अध्ययन करना।
- सागर संभा के औद्योगिक विकास में पंजाब नेशनल बैंक की भूमिका का अध्ययन करना।
- सागर संभाग के औद्योगिक विकास में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सामने आने बाली समस्याओं का अध्ययन करना।
- सागर संभाग के औद्योगिक विकास में पंजाब नेशनल बैंक के सामने आने बाली समस्याओं का अध्ययन करना।

शोध ग्रंथावली

(A) BOOKS

Adarkar, B.N. (1971), Commercial working in India after nationalisation, A.D. Shroff Memorial Trust Bombay.

Basu, S.K. (1965). Theory and Practice of Development Banking, Asia Publishing House Bombay.

Basu, S.K. (1961). Industrial Finance in India A Mukherji and Co. Pvt. Ltd. Calcutta.

Chan, Pei Kang (1949). Agriculture and Industrialisation, Harvard University Press Cambridge.

Das, N. (1961). Industrial Enterprise in India, Orient Longmans Bombay.

David, M.Smith (1971). Industrial Location, United States of America New York.

Deb, Kalipada (1988). Indian Banking Since Independence New Delhi

Desai, Vasant (1979), Indian Banking, Himalaya Publishing House, Bombay.

Desia, Vasant (1988). Development Banking issues and options Himalaya Publishing house bombay.

Corresponding Author

Pankaj Kumar Singh*

Research Scholar, SSSUTMS University, Madhya Pradesh

E-Mail – chintuman2004@gmail.com